उपलब्ध खनिज पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण कब किया गया था ;

(ख) इस सर्वेक्षण के परिणामों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पसलेयर, वल्लियर और कोडायर नदियों के आवाह-क्षेत्र में वर्ष 1978-79 में सर्वेक्षण किए गए थे और उन क्षेत्रों से नमूने लिये गये थे। विघटित हो जाने वाले और पश्चिमी समुद्र-तट के पास जमा हो जाने वाले मोनाजाइट और अन्य महत्वपूर्ण भारी खनिजों का पता लगाने के लिए उद्गम शैल क्षेत्रों का अध्ययन करने की दृष्टि से ये अन्वेषण परम आवश्यक थे।

तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3064. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले और आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों तक फैले 44.5 किलोमीटर लम्बे तटवर्ती इलाकों का सर्वेक्षण किस अवधि के दौरान किया गया था और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उपरोक्त सर्वेक्षण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) वर्ष 1978-79 में केरल के क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जिलों, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले तथा आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुन्टूर जिलों में 44.5 किलोमीटर लम्बे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था और वहां से नमूने एकत्रित किए गए थे। अब तक किए गए सर्वेक्षणों से केरल में मोनाजाइट और उसके साथ पाए जाने वाले अन्य भारी खनिजों की विद्यमानता पाई गई है।

(ख) खनिज-भण्डारों से खनिज निकालने की व्यवहार्यता का पता आर्थिक दृष्टि से लगाने के उद्देश्य से, उन भण्डारों में विद्यमान खनिजों की मात्रा का पता लगाने के लिए यथावश्यक अन्वेषण कार्य विस्तार से किए जायेंगे।

Scheduled Castes Finance Corporations

3065. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Scheduled Castes Finance Corporation have been set up in various States of the country ;

(b) if so, the names of the States where such Corporations have been set up ;

(c) the capital invested in each Scheduled Castes Finance Corporation, State-wise ; and

(d) the advances given in each State by those Corporations so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) to (d). Seventeen States have set up Scheduled Castes Development Corporations. The names of such States are in the enclosed Statement. Particulars of share capital invested after the introduction of the Centrally Sponsored Scheme in 1978-79 and the details of advances given by these Corporations as per the latest figures reported by them are also shown in the attached statement.

Statement

The names of the States where the Scheduled Castes Development Corporations have been set up, particulars of share capital invested and advances given by those Corporations

(Rs. in lakhs)

S. No.	Name of State	Capital invested since 1978-79	Advances reported since 1978 79	
1.	Andhra Pradesh	2,580.25	753.57	Upto 1980-81
2.	Assam	111.78	50.64	Upto June, 1982
3.	Bihar	448.98	23.64	Upto January, 1982
4.	Gujarat	516.25	*	*Complete information not available.
5.	Haryana	292.44	240.62	Upto 15-1-1982
6.	Himachal Pradesh	225.25	80.17	Upto 31-1-1982
7.	Karnataka	333.30	151.59	Upto 1981-82
8.	Kerala	264.86	195.03	Upto 1980-81
9.	Madhya Pradesh	394.33	203.05	Upto January 1982
10.	Maharashtra	253.03	89.79	Upto December 81
11.	Punjab	500.00	379.16	Upto 1980-81
12.	Orissa	204.21	93.44	Upto June 1982
13.	Rajasthan	201.96	43.10	Upto May 1982
14.	Tripura	15.83	0.92	Upto end of March 1982
15.	Tamil Nadu	400.00	264.36	Upto Jan. 1982
16.	Uttar Pradesh	806.00	445.00	Upto June 1982
17.	West Bengal	543.64	32.22	Upto 31-3-1981.

बिहार के पलामू, गया, हजारी बाग, जिलों में पेपर मिल की स्थापना किया जाना

3066. **श्री रणजीत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू, गया और हजारी बाग जिलों में बांस के विशाल वन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन जिलों में हरिजन और आदिवासी अधिक संख्या में हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन जिलों में कोई पेपर मिल नहीं है ;

(घ) क्या कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां एक पेपर मिल की स्थापना करेगी ; और